मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी

सेंट्रल जेल में पोक्सो एक्ट के मामले में बंद कैदी ने बुधवार सुबह पुलिस कन्ट्रोल रूम में फोन कर धमकी दी थी

- पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है।
- पुलिस ने तीन बंदियों को चिन्हित किया है, जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
- मामले में दो जेल वार्डन को निलम्बित कर दिया गया है।

जयपुर, 17 जनवरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने, बुधवार सुबह कंट्रोल रूम में फोन कर जान से मारने की धमकी दी। आनन-फानन में पुलिस कॉल करने वाले का पता लगाकर सेंट्रल जेल पहुंची और आरोपी से पूछताछ की। पुलिस मामला दर्ज कर बंदी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी। इस मामले में दो जेल वार्डन को निलम्बित कर दिया गया है।

घटनानुसार, जयपुर पुलिस कन्ट्रोल रूम में बुधवार सुबह करीब साढ़े सात से आठ बजे के बीच एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने मुख्यमंत्री को शूट करने की धमकी दी। बाद में अपना मोबाइल बंद कर लिया। मुख्यमंत्री को शूट करने की धमकी से पुलिस में अफरा-तफरी मच गई, तुरंत मामला आला अधिकारियों को बताया गया।

पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने तकनीकी टीम को फोन करने वाले की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि फोन जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर से आया है। करीब दोपहर 12 बजे जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद एक कैदी तक पुलिस पहुंची। उसने बताया कि पोक्सो के मामले में बंद बंदी ने उससे मोबाइल मांगकर फोन किया था। दोनों बंदियों के खिलाफ लालकोठी थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी पांच साल से पोक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बंदी से पूछताछ के बाद पता चलेगा कि जेल के अंदर मोबाइल किसने पहुंचाया। पुलिस कन्ट्रोल रूम में फोन करने वाला बंदी ही है या फिर अन्य कोई बंदी भी इसमें शामिल है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। फोन किस मकसद से किया गया, इसका भी पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आरोपी मुकेश उर्फ मुक्का, राकेश और चेतन को चिन्हित किया है। जल्द ही उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार जेल में कोई भी सामान बिना तस्दीक के नहीं जाने दिया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि किसी जेलकर्मी ने ही बंदियों तक मोबाइल पहुंचाया है। इस संबंध में जेल प्रशासन भी जांच कर रहा है। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। सूत्रों के अनुसार मामले में दो वार्डन को निलम्बित किया गया है।

प्र.मंत्री मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही दिन पूर्व रामास्वामी मंदिर के दर्शन करने के कारण वे स्वयं को धन्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि, केरल के कलाकारों ने आज सुबह जो सुन्दर प्रस्तुति दी। उससे उन्हें केरल में भी अवध पुरी जैसी अनुभूति हुई। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और उनकी क्षमताओं को सराहा। लोकसभा चुनावों के महासंघर्ष से पूर्व उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि "मेरे जीवन का एक बड़ा भाग संगठन के लिए पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते गुजरा है। अत: अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि, इस तरह के महासम्मेलन का आयोजन एक मजबूत संगठन द्वारा ही किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि, केरल में आप सभी ने कड़ी मेहनत की है।"

प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की पार्टी बताया और आम चुनावों के मद्देनज़र विकास कार्यों को प्रमुखता से उठाते हुए तीव्र विकास के सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर जोर दिया।

आर.ए.एस.-2023 की उत्तर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

28 जून को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। उसकी प्रारंभिक परीक्षा गत 1 अक्टूबर को हुई। आयोग ने इसी दिन उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांग ली। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कुछ सवालों को लेकर अपनी आपत्तियां आयोग में पेश कर दी। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और गत बीस अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और बोर्ड की किताबों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के प्रश्न सही हैं और याचिकाकर्ताओं ने यदि आरपीएससी प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं तो उनका मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो जाना चाहिए था।

याचिका में गुहार की गई कि मामले में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर इन प्रश्नों का पुन: परीक्षण कराया जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाए। दूसरी ओर आरपीएससी की ओर से कहा कि "विवादित प्रश्न-उत्तरों की एक्सपर्ट से जांच करवा ली है और चार प्रश्नों को डिलीट कर दिया है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी उन्हें भी निस्तारित कर दिया है।" गौरतलब है कि वर्ष 2021 की आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के विवादित सवालों का विवाद भी हाईकोर्ट पहुंचा था। तब हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 240 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे।

विद्युत संकट से बचने के लिये राजस्थान ने 1000 मेगावाट का अस्थाई आवंटन मांगा

- मुख्यमंत्री भजन लाल ने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात कर यह मांग की।
- केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने केन्द्र सरकार के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली/जयपुर, 17 जनवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान प्रदेश में रबी सीजन के दौरान बिजली की बढ़ी हुई मांग की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएन) को आवंटित परसा ईस्ट-कांता बेसिन कैप्टिव कोल माइन्स से खनन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाने के कारण प्रदेश को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे आरवीयूएन की लगभग 4 हजार 340 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त तथा किसानों को 6 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर सिंह से आग्रह किया कि केन्द्र की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों के अनावंटित कोटे से प्रदेश को 1 हजार मेगावाट बिजली का अस्थायी आवंटन किया जाए।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राजस्थान के लिए केन्द्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी के सीजन में प्रतिदिन लगभग 3250 लाख यूनिट से अधिक की बिजली खपत हो चुकी है। अत: बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए।

बैठक के दौरान केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता तथा ऊर्जा विकास निगम के एमडी एम.एम.रिणवा भी मौजूद थे।

वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चार मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया

- बाबूलाल खराड़ा, के.के. विश्नोई, ओटाराम देवासी तथा संजय शर्मा ने मंत्री पद का काम संभाला।

जयपुर, 17 जनवरी (का.सं.)। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भजनलाल सरकार के चार मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया।

कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास, गृह रक्षा विभाग़) ने बुधवार को सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन के कमरा संख्या 6206 में विधिवत् मंत्रोच्चार के बीच पदभार ग्रहण किया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई ने सचिवालय परिसर में स्थित मंत्रालय भवन में अपना पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि, आमजन से जुड़े जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर कार्यकर्ता व संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सचिवालय परिसर में स्थित मंत्रालय भवन में अपना पदभार संभाला। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग आमजन से जुड़ा हुआ विभाग है। आमजन से जुड़े जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे। वन विभाग एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने सचिवालय परिसर में स्थित मंत्रालय भवन में अपना पदभार संभाला।

6 शहीद जवानों के परिवार को एक-एक करोड़ रू. की सम्मान राशि

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। दिल्ली सरकार ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले छह शहीद जवानों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी।

राजस्व मंत्री आतिशी ने बुधवार को बताया कि दिल्ली सरकार सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, दिल्ली सिविल डिफेंस और होम गार्ड के जवानों की बहादुरी का सम्मान करती है। हमारी सरकार वर्दी पहनने वाले हर एक उस जवान की कद्र करती है जो अपनी जान पर खेल कर देश और समाज की रक्षा करते हैं।

आतिशी ने कहा कि सरकार में आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों के परिवार को एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना शुरू किया।

इस सम्मान राशि से शहीदों के परिवारों के नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी।

महाराष्ट्र विधायक अयोग्यता विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई

- विधानसभा अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे व अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका को 10 जनवरी को खारिज कर दिया था।
- इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें आज कपिल सिब्बल ने शीघ्र सुनवाई की मांग की।
- याचिका में कहा गया है कि, स्पीकर का फैसला विधायकों के बहुमत को बेरोटकोट दलबदल करने की अनुमति देता है। यदि अधिकांश विधायकों को राजनीतिक दल माना जाता है तो वास्तविक राजनीतिक दल बहुमत विधायकों की इच्छा के अधीन हो जाता है, जो असंवैधानिक है।

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। उच्चतम न्यायालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेशों को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने की गुहार स्वीकार करते हुए कहा कि, इस मामले में वह सोमवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत के समक्ष सिब्बल ने यूबीटी गुट का पक्ष विशेष उल्लेख के दौरान रखा।

याचिकाकर्ता यूबीटी गुट के सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ 15 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि, निर्णयों की "पूर्ण विकृति" इस तथ्य से स्पष्ट है कि, अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष ने मुख्य निर्विवाद घटना यानी 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण पर विचार ही नहीं किया है, जिसने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि उनके सभी कार्य (21 जून 2022) का उद्देश्य महाराष्ट्र में अपने ही राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को गिराना था।

याचिका में कहा गया, "अयोग्यता का इससे स्पष्ट मामला नहीं हो सकता था। शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की और 30 जून 2022 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सभी प्रतिवादी विधायकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, जो स्वयं स्वेच्छा से हार मानने के समान था।"

याचिका में कहा गया है कि, दसवीं अनुसूची का उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य ठहराना है, जो अपने राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं। हालांकि, यदि अधिकांश विधायकों को राजनीतिक दल माना जाता है, तो वास्तविक राजनीतिक दल के सदस्य बहुमत विधायकों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता निशांत पाटिल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "विधायक दल एक कानूनी इकाई नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए विधायकों के समूह को दिया गया एक नाम है, जो अस्थायी अवधि के लिए सदन के सदस्य होते हैं।"

यू.पी. के 6 शहरों से अयोध्या दर्शन के लिये हैलीकॉप्टर सेवा

- गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा व आगरा से यह सेवा शुरू की जायेगी।

अयोध्या, 17 जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार छह जिलों से राम भक्तों को अयोध्या धाम के दर्शन कराने के लिये हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत लखनऊ से करेंगे। सरकार की ओर से प्रदेश के छह जिलों से शुरू होने वाले हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता ऑपरेटर का चयन किया गया है, जो ऑपरेशनल मॉडल पर हेली सर्विसेस की सेवायें प्रदान करेगा।

राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से मिलेगी। वहीं आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस सुविधा को जल्द शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन भी कराएगी।

एक फरवरी से आयोजित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिल्ली में मंगलवार शाम आयोजित "कर्टन रेज़र" में आयोजकों ने बताया कि, "जयपुर बुकमार्क", एक प्रकाशन सम्मेलन का 11वां संस्करण, जे.एल.एफ. के समानांतर चलेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रकाशक, संपादक, साहित्यिक एजेंट, लेखक, अनुवादक और पुस्तक विक्रेता एकत्रित होंगे। इस वर्ष, "जयपुर बुकमार्क", जो मुख्यत: पुस्तकों के व्यापार पर केन्द्रित रहता है, जे.एल.एफ. के साथ पूरे पाँच दिनों तक चलेगा।

लेखक, इतिहासकार और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के को-डायरेक्टर विलियम डेलरिम्पल ने कहा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हर साल हम अपना ही स्तर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और 2024 अब तक का सबसे बेहतर साल होने जा रहा है। ये अभिव्यक्ति का ऐसा मंच है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र और धाराओं के लोग अपना मत व्यक्त करने को स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, वक्ताओं की हमारी लिस्ट में शामिल हैं: पॉल लिंच, हेर्नन डिआज़, बेन मकिन्त्रे, बोनी गार्मुस, रिचर्ड ओसमान, पीटर फ्रैंकोपन, कोलिन थुब्रों, मैरी बियर्ड, केय बर्ड, कैटी किटामुरा, मोनिका अली, निकोलस शेक्सपियर, डेमों गल्गुट, ल्यूक स्यों, कैथरीन रुंडेल, मेर्वे एमरे, विन्सेंट ब्राउन, अमिया श्रीनिवासन, पैट्रिक रेडेन कीफ, जैरी ब्रोटों और अन्य। यकीनन यह फेस्टिवल बहुत ग्रैंड होने वाला है!

टीमवर्क आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोडूसर, संजॉय के. रॉय ने कहा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की ओर बढ़ते हुए, हमारा मकसद समावेशिता है। हम ऐसे साहित्य की बात करते हैं, जो सबको जोड़ता है और वैश्विक स्तर पर संवाद को बढ़ावा देता है। हमारा फेस्टिवल बहुलवाद, विविधता और बहुभाषावाद का प्रतीक है, जिसमें 24 से अधिक भाषाएं प्रस्तुत होंगी, जिनमें से 16 भारत से हैं।

दिल्ली में घने कोहरे के कारण ऑरैंज अलर्ट

- लगभग 120 उड़ानें प्रभावित, ट्रेन भी देरी से चल रही हैं।

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लगभग 120 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई। इस बीच, घने कोहरे के कारण दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं या रद्द कर दी गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। मौसम एजेंसी ने कहा है कि, इस कड़कड़ाती शीत लहर की स्थिति से कोई राहत नहीं मिलने के आसार हैं और अगले दो से तीन दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा।

आईएमडी ने मंगलवार को दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए बुधवार और गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।

विभाग ने पंजाब और हरियाणा में बुधवार को घने कोहरे और शीत लहर की स्थिति के लिए रेड अलर्ट और गुरुवार को दोनों राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे से संबंधित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को बताया था कि, दिल्ली हवाई अड्डे को कैट तृतीय सक्षम चौथे रनवे के परिसंचालन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उड़ान रद्द होने और देरी के मद्देनजर असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों के बेहतर संचार और सुविधा के लिए एयरलाइंस के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी।

'मंदिर जाने के लिये हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं'

पटना, 17 जनवरी। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अयोध्या में नवनिर्मित भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आज फिर हमला बोला और कहा कि, भाजपा केवल वोट के लिए आस्था का दिखावा कर रही है।

जदयू के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित 'जनसुनवाई' कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मंदिर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण या नेवता की आवश्यकता हमें नहीं है। प्रतिदिन हम अपने घर में भगवान राम की पूजा करते हैं।

कुमार ने कहा कि, हमारी आस्था असली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए आस्था का दिखावा करती है। उन्होंने सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा कि, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता इस मामले को देख रहे हैं। जल्द ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। लघु एवं जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने कहा कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिला है या नहीं इसकी प्रमाणिक जानकारी उनके पास नहीं है।

अखिलेश यादव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का प्रयास पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और उच्च जाति के लोगों को भी एकजुट करना है। उन्होंने यह भी कहा कि, समाजवादी पार्टी ही केवल मात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश में संवैधानिक मूल्यों और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय पदयात्रा के उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी तक पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि, यह यात्रा उत्तर प्रदेश में 11 दिन तक चलेगी, इस दौरान यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के साथ ही कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली एवं राहुल गांधी के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से भी गुजरेगी। अमेठी का वर्तमान में प्रतिनिधित्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी कर रही हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा उ.प्र. के 20 जिलों तक पहुंचेगी और 1074 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इससे पूर्व अखिलेश यादव ने कहा कि, प्रदेश के युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो वर्ष 2024 परिवर्तन और बदलाव का वर्ष है।

उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को भी घेरने की कोशिश की और पूछा कि, उस 40 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. का क्या हुआ जो सरकार ने निवेशकों के सम्मेलन में करने का दावा किया था। वो किधर गए, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है।

डिप्टी सी.एम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सन्, 1994 में विवाह किया था। ठाकुर बुद्ध सिंह को उनके बड़े पुत्र कुंवर अजीत सिंह ने मुखाग्नि दी। जयपुर राज परिवार के उत्तराधिकारी पद्मनाभ सिंह एवं राजकुमारी गौरवी भी अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं।

ठाकुर बुद्ध सिंह की अंतिम यात्रा में पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत, हिमाचल प्रदेश के राज परिवार के उत्तराधिकारी महाराज लक्षराज सिंह सहित अनेकों जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल हुए। पूर्व में दिवंगत ठाकुर बुद्ध सिंह की पार्थिक देह को बुधवार को 11 बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया एवं परंपरागत तरीके से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। कोटडा गढ़ ठाकुर बुद्ध सिंह अपने सरल स्वभाव एवं सामाजिक सरोकार निभाने के लिए क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखते थे।

पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग कांग्रेस में शामिल

- गमांग उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तथा 11 वर्ष केन्द्र में मंत्री रहे हैं।
- वे वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विवादास्पद मतदान करने के लिये जाने जाते हैं।

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं 80 वर्षीय आदिवासी नेता गिरिधर गमांग बुधवार को पुन: कांग्रेस में शामिल हो गए।

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी के ओडिशा प्रभारी अजोय कुमार की मौजूदगी में यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में गमांग के साथ तीन अन्य नेता कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले इन नेताओं में गमांग के पुत्र शिशिर गमांग, पूर्व सांसद हेमा गमांग और संजय भोई भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि, वर्ष 1999 में लोकसभा में मतविभाजन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के एक वोट से गिरने में गमांग का हाथ था, लेकिन गमांग वर्ष 2015 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामलि हो गये थे।

उन्होंने पिछले वर्ष जनवरी में भाजपा छोड़ दी और चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए थे।

ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र के एक प्रमुख आदिवासी नेता, गिरिधर गमांग प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में फिर शामिल किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया है।

गमांग ने कहा कि, कांग्रेस ने उन्हें 11 बार टिकट दिया था और वह 11 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं। वह वर्ष 1972 से वर्ष 2004 के बीच नौ बार कोरापुट लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे।

गमांग ने मई 1999 में लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन के दौरान विवादास्पद रूप से मतदान किया था। वह उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। उस समय उन्होंने फरवरी 1999 में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, लेकिन लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था।

उनका कांग्रेस पार्टी में पुन: स्वागत करते हुए माकन ने कहा कि, गमांग के आने से ओडिशा और देश में भी पार्टी मजबूत होगी और राहुल गांधी की न्याय की लड़ाई में बल मिलेगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908